(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्थाल राव) : (क) कार्यवाही योग्य सभी मामलों में अपराधियों पर कानूनी अदालतों में मुकदमें चलाये गए हैं। मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में इन घटनाओं पर विमर्ष हुआ और यह सहमति हुई कि विशेष सावधानी और तत्परता से ऐसे मामलों पर ध्यान दिया जाये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियां

4276. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये वित्तीय वर्ष 1968-69 में राज्य सरकारों को, राज्यवार अलग अलग, विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति के रूप में कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ख) क्या यह राशि पिछले वर्ष नियत की गई राशि से कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्थाल राव) : (क) सभा पटल पर रखे गये विवरण पत्र में प्रत्येक राज्य के लिए नियतन बताया गया है। **[पुस्कालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT—1763/68]

(ख) नहीं, श्रीमान।

बालमीकि समुदाय के लोग

4277. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री 25 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4975 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वाल्मीकी समुदाय को शौचालयों की किसी भी ढंग से सफाई करने के घृणित कार्य से कब तक मुक्त किया जायेगा ?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्थाल राव) : खुश्क पाखानों के बनाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाकर तथा उनके स्थान पर फ्लश पाखाने बनने के ही मल के शारीरिक तौर पर हटाने की क्रिया बन्द हो सकती है। इसमें बहुत धन खर्च होगा तथा नगरपालिकाओं सम्बन्धी और अन्य कानूनों का संशोधन करना होगा। इस कार्य के लिए वित्तीय संसाधन अभी नजर नहीं आते हैं। अतः अभी किसी विशेष समय-सीमा की ओर इंगित करना सम्भव नहीं है।

अस्पृश्यता उन्मूलन

4278. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए सामाजिक संगठनों का सहयोग मांगा है क्योंकि इस बारे में कानून कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं और उनसे किस प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्थाल राव) : (क) और (ख) : हरिजन सेवक संघ, भारतीय दलित वर्ग लोग, ईश्वर शरण

आश्रम तथा हिन्द स्वीपर्स सेवक समाज ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रचार की योजनाएं शुरु की हैं ।

SOCIAL CONTROL OVER GENERAL INSURANCE

4280. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the criticism of the proposed legislation for social control over General Insurance made at the annual meeting of the General Insurance Employees Association (Eastern Region);

(b) whether it is a fact that representations have been received against this measure not only from the General Insurance Companies but also from the workers Associations;

(c) the main grounds on which the proposed measure is opposed by the different organisations; and

(d) whether in view of this criticism and opposition, Government propose to drop or modify the said measure ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) Copies of resolutions adopted at the Annual General Meetings of two associations namely, Divisional Insurance Employees Association, Jalpaiguri and Gauhati Division Insurance Employees' Association, Gauhati on 18th April 1968 and 21st April, 1968 respectively were received. These asked for nationalisation of general insurance.

(b) and (c). No other representations from workers' associations have been received against this measure. Representations from insurance companies, Chambers of Commerce and a brokers' association have been received, but they contain mainly suggestions for modifications in the Scheme of social control over general insurance as envisaged in the Insurance (Amendment) Bill, 1968.

(d) The suggestions made by the various organisations are receiving attention. The Bill has been referred to a Joint Select Committee of both the Houses.

CRISIS IN PHARMACEUTICALS INDUSTRY

4281. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reported views of Mr. Keith Roy, Head of the Organisation of Pharmaceutical Producers of India in Bombay to the effect that the problems facing the pharmaceutical industry are basically the creation of the 1963 'irrational' price freeze which has plunged the industry in a financial crisis;

(b) if so, whether Government have reviewed the cost of production structure of pharmaceutical industry and if so, with what results;

(c) what is the nature and extent of the financial stringency faced by this industry as a result of the freeze in price of pharmaceutical products without controlling the price of raw material used therefor; and

(d) the steps proposed by Government to ensure regular supply of raw materials of the industry at controlled prices ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH): (a) Yes.

(b) Government had earlier requested the Tariff Commission to examine the price structure of a number of essential drugs produced in the country and their formulations. Their report is awaited.

(c) It is not correct to say that the industry is facing a financial stringency as Government do consider on merits applications for revision of prices on account of increases in the cost of raw materials, containers, packing materials and allow increases wherever justified.

(d) The industry is included in the list of priority industries for the purpose of import of raw materials and spares. Sugar required by the industry is being supplied at controlled rates through the State Governments. As regards the other raw materials which are not subject to price